हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 04 अंक 27 | लखनऊ शनिवार 05 जुलाई 2025 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

घाना की संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले- दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध; जानिए क्यों अहम है ये दौरा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पिछले 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली घाना यात्रा है। पीएम मोदी ने घाना की संसद को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं, संस्कार है। पीएम ने देशवासियों की तरफ से आभार जताते हुए कहा कि कल शाम का अनुभव बहुत ही मार्मिक था, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति जॉन महामा से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना सम्मान की बात है। भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से मैं इस सम्मान के लिए घाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। पीएम बोले- सम्मानित महसूस कर रहा पीएम मोदी ने कहा, 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की सद्भावना और शुभकामनाएं लेकर आया हूं।

'बिना देरी दंडित किए जाएं पहलगाम हमले के दोषी', अमेरिका में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी): अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत के संगठन क्वाड ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। मंगलवार को वाशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसमें मारे गए 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक के स्वजन के प्रति गहरी संवेदना जताई है। हमले के दोषियों को तत्काल सजा दिलाने में मदद करें- भारत इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे इस हमले के दोषियों को तत्काल सजा दिलाने में मदद करें। भारत की मंशा के विपरीत पहलगाम हमले के संदर्भ में संयुक्त बयान में पाकिस्तान या इसकी तरफ से पोषित आतंकी संगठनों का नाम नहीं लिया गया है और न ही भारत-पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले संघर्ष का उल्लेख है। क्वाड ने आतंकवाद की निंदा की संयुक्त बयान में कहा गया है, क्वाड सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद और किसी भी तरह के अतिवाद की कड़ी निंदा करता है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी हम बेहद कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसमें मारे गए लोगों के स्वजन के प्रति हम गहरी संवेदना जताते हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। हम इस हमले के साजिशकताओं, उन्हें वित्तीय सुविधा देने वालों और संगठनों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र के संबंधित नियमों के मुताबिक तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हैं। जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर कही ये बात क्वाड की उक्त बैठक से पहले अपने संबोधन में

आस्ट्रेलिया और भारत के संगठन क्वाड ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा...

अमेरिका जापान आस्ट्रेलिया और भारत के संगठन क्वाड ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे इस हमले के दोषियों को तत्काल सजा दिलाने में मदद करें। संयुक्त बयान में कहा गया है क्वाड सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद और किसी भी तरह के अतिवाद की कड़ी निंदा करता है।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पहलगाम हमले के बारे में साफ तौर पर कहा था कि भारतीय नागरिकों पर इस तरह का आतंकी हमला आगे होगा तो फिर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जयशंकर ने यह भी उम्मीद जताई थी कि क्वाड के सहयोगी देश सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की संवेदनाओं को समझेंगे।क्वाड के विदेश मंत्रियों ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना की बढ़ती तैनाती पर गंभीर चिंता व्यक्त की। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों को रेखांकित किया साथ ही स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र और कानून के शासन, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए क्वाड की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। चीन का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं करते हुए उन्होंने कहा, 'हम ताकत या दबाव के जरिये यथास्थित बदलने की किसी भी एकतरफा कोशिश के प्रति अपना कड़ा रिाध दोहराते हैं।' क्वाड के विदेश मंत्रियों ने खासतौर पर खतरनाक एवं उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों को रेखांकित किया जिनमें अपतटीय संसाधनों के विकास में हस्तक्षेप, नेविगेशन एवं ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता में बार-बार रुकावट डालना और सैन्य विमानों, तटरक्षक पोतों व समुद्री जहाजों के खतरनाक अभ्यास शामिल हैं। उन्होंने आर्बिटल ट्रिब्युनल के 12 जुलाई, 2016 के फैसले को लागू करने की जरूरत पर बल दिया। ट्रिब्युनल ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के विरुद्ध फैसला सुनाया था। म्यांमार की खराब होती स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की उन्होंने म्यांमार की खराब होती स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों की अचानक कमी और भविष्य में निर्भरता पर गहरी चिंता जताई।

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर केंद्र और राज्य सरकारों पर साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार के स्तर पर चुप्पी तथा बेरुखी देखी जा रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि यह "सिस्टम" किसानों को मार रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने "पीआर" का तमाशा देख रहे हैं। राहुल गांधी ने ह्यएक्स' पर पोस्ट किया, "सोचिए.. सिर्फ तीन महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं। ये 767 उजड़े हुए घर हैं। 767 परिवार, जो कभी नहीं संभल पाएंगे। और सरकार? वह चुप है। बेरुखी से देख रही है।" उन्होंने दावा किया, "किसान हर दिन कर्ज.में और गहराई तक डूब रहा है - बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है.. लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वे कर्ज. माफी की मांग करते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।" कांग्रेस नेता ने कहा, "लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपये हैं? उनके कर्ज मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ रुपये का एसबीआई फ्रॉड। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "मोदी जी ने कहा था, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे - आज हालत ये है कि अन्नदाता की ज़िंदगी ही आधी हो रही है।" राहुल गांधी ने कहा, "यह सिस्टम किसानों को मार रहा है - चुपचाप, लेकिन लगातार.... और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं।" भारतीय जनता पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए "एक्स" पर एक चार्ट साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में 55,928 किसानों ने आत्महत्या की। मालवीय ने कहा, मृतकों को गिनने की राजनीति घृणित है, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है।" भाजपा नेता ने कहा कि अपना मुंह खोलने से पहले राहुल गांधी को महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान द्वारा "किए गए पाप" को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा, "पहले बताएं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा (एसपी) सरकार के 15 वर्षों में 55,928 किसानों ने आत्महत्या क्यों की?"

पर्यावरण और वन संरक्षण पर मोदी सरकार का रिकॉर्ड भरोसे के लायक नहीं: जयराम रमेश

नई दिल्ली (एजेंसी): कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार का अब तक का 'ट्रैक रिकॉर्ड' ऐसा नहीं रहा है कि उस पर पर्यावरण, वन संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर पूरा ध्यान देने के लिए भरोसा किया जाए। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने कई नागरिक संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए हालिया पत्र का उल्लेख किया। रमेश ने ह्यएक्स' पर पोस्ट कर कहा, "हाल ही में 150 नागरिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वन अधिकार अधिनियम, 2006 को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई है।" उन्होंने कहा, "पत्र में पांच अहम बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा दिए गए खुद के ऐसे बयान..., जिनमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 को देश के प्रमुख वन क्षेत्रों के क्षरण और नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।" उन्होंने कहा, "वन अतिक्रमण को लेकर कानूनी तौर पर अपुष्ट आंकड़ों को लगातार संसद और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सामने पेश किया गया। जून, 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा देशभर के टाइगर रिजर्व से लगभग 65,000 परिवारों को बेदखल करने का आदेश दिया गया।" उन्होंने पत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पिछले एक दशक में वन क्षेत्र में आई गिरावट के लिए वन अधिकार अधिनियम को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया। रमेश ने कहा, " 2023 में बिना पर्याप्त संसदीय चर्चा के पारित किया गया वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन और उसके तहत लागू किए गए ह्यवन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023' -का प्रतिकूल असर वनों पर पड़ा है।" उनके मुताबिक, ये सभी मुद्दे विशेष रूप से आदिवासी और वन क्षेत्रों में रहने वाले अन्य समुदायों के लिए अत्यंत अहम हैं, जिनकी आजीविका जंगलों पर निर्भर है तथा ये भारत की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी हैं। रमेश ने

संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला बोले- भाजपा अब डी गैंग बन गई है...

महाराष्ट्र (एजेंसी): आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। राउत ने आरोप लगाया कि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है और पूरी तरह बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहा है। राउत ने कहा, "चुनाव आयोग अब केवल नाम का बचा है, कोई सुनवाई नहीं होती और न ही कार्रवाई। आयोग अब बीजेपी में ही शामिल हो गया है। ऐसे में जनता न्याय की उम्मीद किससे करे?" संजय राउत ने आरोप लगाया कि नाशिक में शिवसेना (यूबीटी) के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि असली अपराधी भाजपा में शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कल तक जिन्हें गुनहगार" कहा जा रहा था, वे अब मंत्रियों के बंगलों पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कल को पहलगाम हमले के आतंकी भी बीजेपी में शामिल हो जाएं, राउत ने तंज कसते हुए कहा। दिशा सालियान केस पर फडणवीस से माफी की मांग राउत ने दिशा सालियान मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अब जब सच सामने आ चुका है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे की छवि खराब करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे फडणवीस और शिंदे को आदित्य ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी डरपोकों की गैंग बन गई है राउत बीजेपी में हालिया शामिल हो रहे नेताओं को लेकर संजय राउत ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बलात्कारी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज अब सीधे भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों का एक ही उद्देश्य, सत्ता में बने रहना, राजनाथ सिंह का तीखा हमला- नफरत की राजनीति करती है विपक्ष

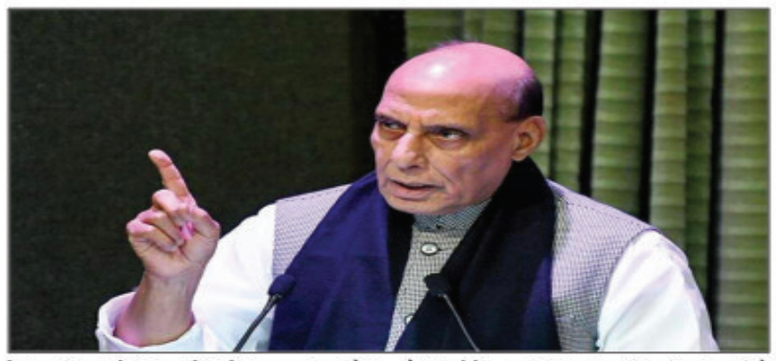

पटना (एजेंसी): रक्षा मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसे दलों का सत्ता में बने रहना ही उद्देश्य है। राजनाथ सिंह ने बुधवार को यहां प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस और राजद को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों का एक ही उद्देश्य है, सत्ता में बने रहना, जबकि भाजपा का उद्देश्य भारत के हर नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है, ऐसी नीतियां बनाना है, जिनमें समाज के हर वर्ग का विकास हो। सभी को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, यह भी हमारी सरकार ने ही किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सभी भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत हैं। केन्द्रीय मंत्री ने इस साल होने वाले चुनाव में फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की दो तिहाई बहुमत से सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि राजग की सरकार के कार्यकाल में बिहार में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार के चाहे मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों या मंत्री, किसी पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष नफरत की राजनीति करती है, जबकि भाजपा सेवा और विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता का फर्ज है कि वह हर घर तक पहुंचे और मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दे। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि यदि कोई बिहार का खोया गौरव लौटा सकता है, तो वह भाजपा और राजग है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसका मकसद सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि समाज को जोड़ना और हर व्यक्ति की गरिमा को बनाये रखना है। BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता सेवा भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हुआ हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। सिंह ने कहा कि यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, बल्कि एक संकल्प सभा है, उस संकल्प की सिद्धि के लिए जो बिहार और भारत दोनों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में यह सिद्ध किया है कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाये। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है, यह उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है

'भाजपा ने गुजरात का किया बेड़ा गर्क', केजरीवाल बोले- युवा 'आप' से जुड़े और राज्य की कमान संभालें

गुजरात (एजेंसी): आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2027 में गुजरात जीतने को लेकर मेगा प्लान बनाया है। इस बाबत बुधवार को उन्होंने अहमदाबाद से गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान का आगाज किया। उन्होंने गुजरात के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि 9512040404 नंबर पर मिस्ड कॉल कर 'आप' से जुड़कर ईमानदारी, विकास व बदलाव की इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनें और गुजरात की बागडोर संभालें। विसावदर की जीत सिर्फ एक सीट की नहीं है, बल्कि ईमानदारी की जीत है। अब यह बदलाव पूरे गुजरात में गूंजेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल बीजेपी की नौकरी करती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी देश और गुजरात के लोगों की सेवा करती है। 30 साल से गुजरात में कोई विकल्प नहीं होने से बीजेपी को घमंड हो गया था कि जनता कहां जाएंगी, वोट तो उसे ही देगी। लेकिन अब गुजरात में 'आप' एक सशक्त विकल्प बन चुकी है। 2027 में 'आप' सरकार बनाएगी। जनता का राज आएगा और भ्रष्टाचारियों का राज जाएगा। इस दौरान गुजरात प्रदेश प्रभारी गोपाल राय, सह प्रभारी गुलाब सिंह यादव, दुर्गेश पाठक, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा, जाम जोधपुर विधायक हेमंत खवा, विसावदर विधायक गोपाल इटालिया एवं गुजरात संगठन मंत्री मनोज सोरठिया उपस्थित रहे। अब गुजरात बदलाव चाहता है- केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को विसावदर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि विसावदर की जीत कोई मामूली जीत नहीं है। विसावदर की जीत के जरिए भगवान बड़ा संदेश देना चाहता है कि गुजरात अब बदलाव चाहता है। यह जीत कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसी सीट से 2022 में हम जितने वोट से जीते थे, इस बार उसी सीट पर हुए उपचुनाव में हम तीन गुना ज्यादा वोटों से जीते। अक्सर उपचुनाव में राज्य में सत्ताधारी दल की जीत होती है। गुजरात में बीजेपी की 30 साल से सरकार है। बीजेपी का प्रशासन पर जबरदस्त जकड़ है। बीजेपी को साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी गलत काम करने से परहेज नहीं है। बीजेपी ने गुंडागर्दी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने गोपाल इटालिया को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी इतने प्रचंड मतों के अंतर से जीतना कुदरत का बड़ा संदेश ही है। बीजेपी ने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान जनता के जरिए बोलते हैं। विसावदर में जीत दिलाकर भगवान कहना चाहते हैं कि गुजरात में कांग्रेस ने 30 साल तक राज किया और 30 साल से बीजेपी राज कर रही है, लेकिन अब समय का चक्र घूम गया है और बीजेपी के जाने का समय आ गया है। अब गुजरात की सत्ता में नई और देशभक्त पार्टी आएगी जो अच्छा काम करेगी। बीजेपी-कांग्रेस ने मिलकर गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया है। सूरत जैसे शहर में बाढ़ आई है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोग यहां करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रखे हैं। पानी में टेलीविजन, सोफे डूब गए। विसावदर उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए मैं जूनागढ़ जाने के लिए राजकोट में उतरा। आज दुनिया भर में शानदार सड़कें बन रही हैं, जिन पर गाड़ियां 100-150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। लेकिन राजकोट से जूनागढ़ जाने में मुझे 3.30 घंटे लग गए। 35 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलानी पड़ी। 30 साल में बीजेपी सड़क तक नहीं बना सकी। जनता ने बीजेपी को अच्छा काम करने के लिए चुना था अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1995 में बीजेपी की गुजरात में सरकार बनी थी

सम्पादकीय...

लंबी विदेश यात्रा पर मोदी

एक महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। इस बार घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया इन पांच देशों की यात्रा श्री मोदी कर रहे हैं, जो 8 दिनों की होगी। हमेशा की तरह इस बार भी सरकारी बयान में बताया गया है कि विदेश यात्रा का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करना है। भारतीय प्रधानमंत्री इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और आपसी सहयोग और विकास पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, हमेशा यही तो होता है कि दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से श्री मोदी की हाथ मिलाते, गले मिलते, सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हंसते-मुस्कुराते चर्चा करते और विभिन्न करारों पर हस्ताक्षर करते तस्वीरें आती हैं। देश को बताया जाता है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत को विकसित करने के लिए सारे देश मदद कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों की हकीकत तब समझ आती है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बड़े से भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अलग-अलग देशों में अपना पक्ष रखने के लिए भेजना पड़ता है। विदेश नीति की परीक्षा पहलगाम हमले या ऑपरेशन सिंदूर जैसी असामान्य स्थितियों में ही होती है, और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही चाहिए कि इस परीक्षा में मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम को लेकर हो रहे बेहूदे दावे थम ही नहीं रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन दावों को खारिज नहीं किया है तो अब तक भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी सफाई देनी पड़ रही है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर से अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक के लिए हो रहे एक साक्षात्कार में फिर यह सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा है कि श्संघर्ष को रोकने के लिए व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। क्या इससे व्यापार समझौते की बातचीत पर कोई असर पड़ा है?य इस सवाल से साफ समझ आता है कि ट्रंप के दावे को अब दुनिया भी मान रही है। अगर श्री मोदी ने पहले ही बार में इस पर आपत्ति जताई होती तो शायद इस तरह के सवाल नहीं उठते। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं और विदेश मंत्री सफाई दे रहे हैं कि 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था तो वह भी उसी कमरे में मौजूद थे। जयशंकर ने कहा कि तब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत पाकिस्तान की धमकियों से डरेगा नहीं बल्कि इसका जवाब देगा। सोचने वाली बात यह है कि जो बयान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले दे चुके हैं, जिसे अभी विदेश मंत्री एस.जयशंकर भी कह रहे हैं, उस बात को अब तक प्रधानमंत्री मोदी अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते। आखिर किसने उनके मुंह पर चुप की उंगली रखी है। क्या लंबी-लंबी विदेश यात्राओं से ये उंगली हटेगी या मुंह पर ताले और बढ़ेंगे। अभी कनाडा में जी-7 की बैठक में श्री मोदी शामिल हुए थे, और पखवाड़े बाद ही अब ब्रिक्स सम्मेलन के लिए वे रवाना हुए हैं। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल सभी देश अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए करते हैं, हालांकि इनमें असली जोर व्यापार का होता है, क्योंकि इस समय पूरी वैश्विक राजनीति कारोबारी हितों के इर्द-गिर्द घूम रही है। ऐसे में श्री मोदी की मौजूदा यात्रा में भी व्यापार को बढ़ाने के संकेत अलग-अलग तरीकों से दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले घाना जाएंगे और यात्रा के अंतिम चरण में स्वदेश वापसी के समय नामीबिया जाएंगे। ये सारे देश अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी हैं और कहा जा रहा है कि इससे ग्लोबल साउथ के भारतीय एजेंडे को नई धार मिल सके। बता दें कि ग्लोबल साउथ शब्द पहली बार 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी ने इस्तेमाल किया था। इसमें अमूमन वही सारे देश हैं, जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। दुनिया के उत्तरी हिस्से में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देशों से अलग दक्षिण हिस्से में आने वाले अफ्रीकी, द.अमेरिकी और कई एशियाई देशों को ग्लोबल साउथ के तहत रखा जाता है। इनकी चिंताएं और सरोकार लगभग एक जैसे हैं। हालांकि इनमें चीन का दबदबा है और वहीं आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों का रुख भी कई बार ग्लोबल नार्थ की तरफ ही दिखाई देता है। ऐसे में ग्लोबल साउथ के बैनर तले जो नयी वैश्विक व्यवस्था बनाने की कोशिश चल रही है, वह कितनी कारगर होगी, कहा नहीं जा सकता। वैसे अभी श्री मोदी जिन देशों में जा रहे हैं, या ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं, उनसे भारत के संबंध पहले ही अच्छे रहे हैं। इन सभी देशों में प.नेहरू की बनाई विदेश नीति के कारण ही भारत की साख मजबूत बनी हुई है।

राशिफल

मेषः- आज कुछ अच्छे आसारों से मन प्रफुल्लित रहेगा। रोजगार संबंधी यात्रा में अवरोध संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार है। शिक्षा क्षेत्र में जुड़े सभी छात्रों को परिश्रम करने की आवश्यकता है।

बृषभ :- स्वयं पर भरोसा कर योजनाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करें। संबंधों में सरल व व्यवहारिक बनने की कोशिश करें। आर्थिक चिंता संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार हैं।

मिथुनः- किसी महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध मन को हतोत्साहित करेगा। संबंधों के प्रति नयी शिकायतें संभव। किसी विद्वान के विचारों से प्रभावित मन मे उत्साह का संचार होगा। क्रोध पर नियंत्रणरखें।

कर्क :- कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा-प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव। पत्नी के स्वास्य का ध्यान रखें।

सिंह :- किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। शिक्षा-प्रतियोगिता की दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा।

कन्या :- समस्याओं के समाधान हेतु मन नए युक्तियों पर केन्द्रित होगा। महत्वपूर्ण कायरे के प्रति आलस्य न करें। छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित न हो। शिक्षा-प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा।

तुला :- मन सकारात्मक विचारों से प्रभावित होगा। नाजुक संबंधों में सन्तुलित व मधुर वाणी का प्रयोग करें। कोई आपका अपना बिगड़े हुए सम्बन्धों मे सुधार कराएगा। किसी कार्य से संपन्न होने के आसार हैं।

वृश्चिक :- सभी प्रकार के दायित्वों की पूर्ति हेतु सन्तुलित योजना पर चलें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में संबंधों का सहयोग प्राप्त होगा। विरोधियों की प्रबलता से कठिनाइयां संभव। मधुर वाणी का प्रयोग करें।

धनु :- नए समीकरण लाभकारी कार्य क्षमता के परिचायक होंगे। प्रणय सम्बनध मे प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आय-व्यय मे सन्तुलन बनने का प्रयत्न करें। आलस्य का त्याग करें। रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

मकर :- कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा-प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव। कटु शब्दों का प्रयोग न करें।

कुंभ :- पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर आप उत्साहित होंगे। नियोजित कार्यकुशलता प्रगति के लिए आशान्वित होंगे। सुखद कायरे की व्यस्तता रहेगी। भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी।

मीन :- क्षमता से परे किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना हानिकार हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा मे लापरवाही ना करें।

योगी बंदर की लीला और जनजागरुकता

सर्वमित्रा सुरजन

सोशल मीडिया पर रील्स, मीम्स बनाने का पागलपन, इस मंच को झूठी, नफरती खबरें फैलाने का जरिया बनाना, हर वर्ग के लोगों का अधिकाधिक वक्त सोशल मीडिया पर बीतना, इन सब बातों पर पिछले कुछ वक्त में काफी चिंता बढ़ी है। समाजशास्त्रियों के लिए यह अध्ययन का नया विषय ही बन गया है कि संचार क्रांति का यह कैसा दौर आया है, जिसमें एक के बाद एक नयी लहर उठती है। मियादी बुखार की तरह कभी भी कोई भी चीज वायरल हो जाती है। नैतिक-अनैतिक के बीच का हर अंतर सोशल मीडिया पर मिटाया जा चुका है। न किसी का लिहाज, न कोई पाबंदी, बस जिसे जो कहना है, लिखना है, दिखाना है, सुनाना है, वह अपने मन की करे। असल मायनों में मन की बात सोशल मीडिया पर चलती है। इसमें कभी कुछ ऐसा हो जाए, जिस पर बड़ा विवाद हो, तब कुछ पोस्ट्स को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन तब तक उसका स्क्रीन शॉट सुरक्षित रख लिया जाता है या सामग्री ही किसी और तरीके से स्टोर कर ली जाती है। आसान शब्दों में, एक बार जो चीज सोशल मीडिया पर आ गई, उसे नष्ट करना मुश्किल होता है। ऐसे सोशल मीडिया के दौर में बंदर लीला योगी के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें एक बंदर साधु या योगी की वेशभूषा में बैठा हुआ नजर आता है और उसकी लीला यह है कि यह योगी बंदर ज्वलंत सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर धीर-गंभीर बातें करता है। देश में शिक्षा की बदहाली से लेकर टीआरपी के लिए मीडिया की उछलकूद सब पर इस योगी बंदर का ध्यान है और वह अपने भक्तों को इस पर प्रवचन देता है कि उसकी निगाह में यह सही है या गलत। एक वीडियो में कथावाचक बना बंदर कहता

है, श्जिस देश में सरकारी स्कूलों की छतें टपकती हों और मंदिर सोने से जड़े हों, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। अगर मंदिरों का पैसा स्कूलों में लगाया जाए तो भारत विकसित हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ लोगों को डर है कि अगर बच्चे पढ़ गए, तो सवाल पूछेंगे। वहीं एक प्रवचन में योगी बंदर ने कहा कि श्अगर मंदिर में चढ़ाया गया पैसा भगवान का है, तो फिर वो जनता में क्यों नहीं बांटा जाता?पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मीडिया के बड़े हिस्से ने जिस किस्म की रिपोर्टिंग की, उसकी धज्जियां भी योगी बंदर ने उड़ाई हैं। इसमें उसने कहा है कि अगर सर्कस देखना हो तो बाहर मत जाना, मोबाइल पर टीवी चैनल खोल देना। टीआरपी के लिए इतने मरे जा रहे कि हमारे सैनिक बार्डर पर खड़े हैं और ये कह रहे हैं इस्लामाबाद पर कब्जा। ये वही लोग हैं, जिन्होंने मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी की लोकेशन ब्रॉडकास्ट कर दी और कहीं न कहीं उससे आतंकवादियों को मदद मिली। वो कहते हैं कि भारत अब विकसित होने ही वाला है। अरे लोगों के पास स्कूल-कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, और तुम हवा में भारत को विकसित बना रहे हो। एक अन्य वीडियो में योगी बंदर ने बताया है कि अगर श्री राम भारत के प्रधानमंत्री होते तो कैसा भारत होता। जिसमें आस्ट्रेलिया की तरह प्रदूषण मुक्त हवा होती। पुलिसवाले भाग-भागकर एफआईआर लिखते, भले सामने नेता का बेटा ही क्यों न हो। भारत का ट्रेड और एग्रीकल्चर फल फूल रहा होता। सबको समान न्याय मिलता, छुआछूत को मिटा दिया जाता, जाति को काम के आधार पर किया जाता, न कि जन्म के आधार पर। सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई होती। मंदिरों में भगवान का नाम लेकर साइंस और टेक्नॉलॉजी का ज्ञान साझा किया जाता। किसान खुदकुशी नहीं करते। वोटरों को बांटने के लिए नफरती भाषण नहीं दिए जाते। आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या नहीं होती। गंगा नदी एकदम साफ होती। आम आदमी के कोर्ट केस 20-20 साल नहीं चलते। मूवी का हीरो एक साथ सौ लोगों की हत्या करे तो उसे ग्लोरिफाई नहीं किया जाता और ऐसी फिल्मों की भारत में कोई जगह नहीं होती। अगर किसी कारण से जंगल काट भी दिए जाते तो ट्राइबल लोगों को गर्वमेंट आईडी दी जाती और उनकी शिक्षा का ख्याल रखा जाता। एक और वीडियो में योगी बंदर ने कहा कि अगर आज हनुमान जी होते तो कहते कि मुझे तुम्हें अपना वंशज कहने में शर्म आती है। एक कंपनी का सीईओ भी बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाता है। अरे तुम सीईओ हो कि चूहे हो। हमने तो रावण को घर में घुसकर मारा था, तुम एक बिल्ली से डर गए। तुम विश्वगुरु कैसे बनोगे, तुम डेढ़ सौ करोड़ हो, लेकिन डरे हुए हो। वो बताते कि हमने राम सेतु मंत्र फूंककर नहीं बनाया था, नल और नील नाम के दो इंजीनियरों से बनवाया था। वो तुम्हें जागृत करते कि जहां समाज डरा हुआ हो, वहां साइंटिस्ट कम और गुलाम ज्यादा पैदा होते। भारत का अपना एआई क्यों नहीं बन पाया, इस बारे में भी योगी बंदर ने बताया है कि हमारे पास डेटा

एक वीडियो में कथावाचक बना बंदर कहता है, श्जिस देश में सरकारी स्कूलों की छतें टपकती हों और मंदिर सोने से जड़े हों, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। अगर मंदिरों का पैसा स्कूलों में लगाया जाए तो भारत विकसित हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ लोगों को डर है कि अगर बच्चे पढ़ गए, तो सवाल पूछेंगे। वहीं एक प्रवचन में योगी बंदर ने कहा कि श्अगर मंदिर में चढ़ाया गया पैसा भगवान का है, तो फिर वो जनता में क्यों नहीं बांटा जाता?पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मीडिया के बड़े हिस्से ने...

ही नहीं है, सारा डेटा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के पास है। अमेरिका ने चैटजीपीटी, चीन ने डीप सीक बना लिया। हमारे इंजीनियरों ने जब कू ऐप बनाया था तो उसके जरिए डेटा इकट्ठा हो सकता था, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला और चार साल में ही कू ऐप बंद हो गया। श्रीराम के शासन का भारत, हनुमानजी की सीख से लेकर मीडिया की नैतिकता, अंधविश्वास, विज्ञान और टेक्नॉलॉजी सभी विषयों पर यह एआई जनरेटेड योगी बंदर प्रवचन देता है। इसमें जो बातें कहीं गई हैं, उन्हें अक्सर लोग आपसी चचाओं में करते हैं, लेकिन अब माहौल ऐसा हो चुका है कि इन्हें खुलकर कहने की हिम्मत नहीं दिखाई जा रही। जो ऐसी हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इस एआई जनरेटेड बंदर को जिसने भी बनाया है, उसने ज्वलंत मुद्दों को रोचक तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम किया है। धर्मभीरू भारतीय समाज को उसकी भलाई के लिए सलाह देने का यह तरीका कारगर है कि उसमें धर्म का आवरण डाल दिया जाए। यही बंदर अगर शिक्षक, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, किसान, मजदूर या नेता की तरह दिखाई देता, तब भी उसकी बातें रोचक और जागरुक करने वाली तो होतीं, लेकिन उनका वह असर नहीं दिखाई पड़ता, जो अब दिख रहा है। बंदर बैठकर प्रवचन दे रहा है, यह बात तो रोचक है ही, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बंदर रूढ़िवादिता को खारिज कर आधुनिक युग के हिसाब से चलने की सलाह भक्तों को दे रहा है। वर्ना इस समय समाज की बुद्धि ऐसे प्रवचनकारियों ने भ्रष्ट की हुई है, जो हथेली को मोबाइल बनाकर हनुमानजी से सीधे बात करने का ढोंग करते हैं और भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। लोगों में इतनी चेतना भी दिखाई नहीं देती कि वे पूछ सकें कि अगर हनुमान जी से सीधे बात हो ही जाती है, तब हथेली को मोबाइल बनाने की भी क्या जरूरत, इस सीधे कनेक्शन के लिए तो किसी भी चीज की दरकार नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाकर ही ऐसे ढोंगी खुद ऐशो आराम का सारा सामान जुटा लेते हैं। दुनिया की सैर करते हैं, महंगे कपड़े, जूते, चश्मे पहन कर रौब झाड़ते हैं कि सवाल मत पूछना वर्ना और महंगा पहन कर चिढ़ाऊंगा।

कुछ खास...

हिन्दी को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनायें

ललित गर्ग

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हिन्दी विरोध की राजनीति अब महाराष्ट्र में भी उग्र से उग्रतर हो गयी, इसी के कारण त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। आखिरकार राजनीतिक दबाव, लंबी रस्साकशी और कशमकश के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई

से जुड़े मुद्दे पर यू-टर्न लेते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। विदित हो कि केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। राजनीतिक आग्रहों एवं दुराग्रहों के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब, महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी का संकट वास्तव में एक गहरे सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। यह केवल भाषाई नहीं, बल्कि अस्मिता, पहचान और सह-अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जबकि भाषा को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाना चाहिए। क्योंकि जब मराठी और हिंदी एक-दूसरे की सहयोगी बनेंगी, तभी महाराष्ट्र और भारत दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा और तभी महाराष्ट्र राष्ट्रीयता से जुड़ते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। हिन्दी को हथियार बनाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ-पांव फूलने लगे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। ठाकरे बंधुओं का हिन्दी विरोधी आंदोलन दिनोंदिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह नहीं मोड़ सकती। यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र में पूर्व में एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बड़ा नहीं था, पर आज जब ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, समूचे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव जिसे मिला हुआ है, जहां समूचे देश के लोगों बसे है, जिसे सांझा-संस्कृति का गौरव प्राप्त है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठी मानुष की शक्ति से हार गई, पर वे इस बात को छिपा रहे हैं कि हारी सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्र-भाषा हिंदी हारी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है। भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परंतु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है। फडणवीस सरकार की ताजा घोषणा यह दर्शा रही है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक ताकतवर राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मॉनसून सत्र को हंगामेदार बनाने पर आमादा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोध की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरूआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों की निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के दशक से भाजपा के गठबंधन में शिवसेना की राजनीति भी हिंदी से हिंदू की ओर मुड़ती गई। ऐसे में निश्चित ही मराठा राजनीति से हिन्दी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अब तक तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के लिए जाना जाता था, पर इधर तीखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। दुनिया की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली हिन्दी भाषा अपने ही देश में उपेक्षा एवं राजनीति की शिकार है। अब केन्द्र सरकार के साथ-साथ हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। हिन्दी भाषी प्रांतों को अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदीभाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए। क्या हिंदी प्रदेश के नेता इससे सबक लेंगे? हालांकि, जिस तरह की त्रासद भाषा-राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उससे यही लगता है कि इसके लिये बनी समितियों में बैठने वाले विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया जाएग और राष्ट्रीयता पर क्षेत्रीयता की जीत हासिल हो जाएगी। महाराष्ट्र में बढ़ते हिन्दीभाषियों के अनुपात को देखते हुए देर-सबेर हिन्दी को अपनाना ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र, कुल आबादी में हिंदीभाषियों का बढ़ता अनुपात हिन्दी के पक्ष में है। 2001 की जनगणना के मुताबिक हिंदीभाषियों की संख्या मुंबई में 25.9 प्रतिशत और मराठीभाषियों की 42.9 प्रतिशत थी जो 2011 में क्रमशः 30.2 प्रतिशत और 41 प्रतिशत हो गई। महाराष्ट्र में इसी अवधि में जहां मराठीभाषी आबादी 76 प्रतिशत से 73.4 प्रतिशत पर आ गई, वहीं हिंदीभाषियों का अनुपात 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया। इसीलिये हिंदी लादने के इस फैसले ने न केवल उद्धव और राज ठाकरे को आक्रामक रूप में सामने ले आई बल्कि 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। 5 जुलाई को होने वाली हिन्दी विजय रैली पर महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर सुर में सुर मिलाने वाले उद्धव और राज ठाकरे को सियासी हौसला मिल गया है। जिसे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ माना जा रहा, लेकिन साथ ही सवाल है कि उद्धव और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री कब तक बरकरार रहेगी। हिंदी बनाम मराठी विवाद को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया गया है। कुछ स्थानीय दलों ने हिंदी भाषी प्रवासियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को निशाने पर लेकर हिंदी भाषा पर परोक्ष रूप से प्रहार किया है। इससे न केवल भाषा के नाम पर लोगों में दूरी बढ़ी है, बल्कि महाराष्ट्र की समावेशी छवि को भी आघात पहुंचा है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों, विशेषकर मुंबई, ठाणे, पुणे, और नासिक में बड़ी संख्या में हिंदीभाषी समुदाय निवास करता है।

नये भाजपा अध्यक्ष के चयन में और देरी संभव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में दशहरा के दिन अपना शताब्दी वर्ष मनायेगा। अधिकांश संगठन तो अपनी शताब्दी के करीब पहुंचने से पहले ही पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं या यहां तक कि विघटित हो जाते हैं। परन्तु आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा भाजपा के माध्यम से भारत पर शासन कर रहा है। लेकिन शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर इसके सरसंघचालक मोहन भागवत ने विडंबनापूर्वक संगठन पर अपना अधिकार और नियंत्रण खो दिया है। जहां पिछले सरसंघचालकों के शब्दों को भगवा पारिस्थितिकी तंत्र ने आज्ञाओं की तरह माना, वहीं शताब्दी वर्ष में भागवत के उपदेशों को कोई नहीं मानता। यह अब कोई रहस्य नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझ कर और योजनाबद्ध तरीके से उनकी छवि और विश्वसनीयता को कम किया है। अपने शासन के ग्यारह वर्षों के दौरान, आरएसएस प्रचारक मोदी ने आरएसएस मुख्यालय में भागवत से केवल एक बार मुलाकात की। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने भागवत के सुझावों और सलाह की परवाह नहीं की। आरएसएस और खासकर भागवत भाजपा के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरएसएस नेता के लिए जोर दे रहे हैं। लेकिन मोदी का उनके निर्देश की अनदेखी करना उनके तिरस्कार का स्पष्ट प्रमाण है। वास्तव में पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने 2024 में ही लोकसभा चुनाव से काफी पहले यह कहकर इस अनादर को प्रकट कर दिया था कि श्भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। जब से नड्डा ने 2023 में अपना कार्यकाल पूरा किया है, तब से भागवत पार्टी प्रमुख के रूप में आरएसएस नेता के लिए जोर दे रहे हैं। लेकिन नड्डा की औपचारिक सेवानिवृत्ति के ढाई साल बाद भी, उनका भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी है। कारण साफ है। मोदी को एक ऐसे अनुचर की जरूरत है जो उनके आदेशों का पालन करे। उन्हें समानांतर सत्ता केंद्र पसंद नहीं है। भाजपा अध्यक्ष के रूप में आरएसएस नेता उनके वर्चस्व के लिए संभावित खतरा साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि मोदी जानबूझ कर उनकी दलीलों को नजरंदाज कर रहे हैं। गोवा में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था, तब भगवा कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मोदी की राष्ट्रीय अपील और लोकप्रियता नहीं थी। लालकृष्ण आडवाणी के साथ भागवत ने उन्हें आगे बढ़ाया। निर्वाचित होने के बाद मोदी का पहला काम आडवाणी को अलग-थलग करना और उन्हें निष्क्रिय बनाना था। लेकिन उस समय भागवत को हटाने या अलग-थलग करने की हिम्मत वे नहीं कर पाये, क्योंकि वे आरएसएस प्रमुख थे। एक सुनियोजित चाल के तहत उन्होंने उन्हें नजरंदाज करना शुरू कर दिया, जिससे यह संदेश गया कि भागवत भाजपा के लिए किसी काम के नहीं हैं। मोदी ने भगवा पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सफलतापूर्वक ऐसी स्थिति बना दी, जहां भागवत की सलाह अवांछित थी। 2023 में ही आरएसएस के कई शीर्ष नेताओं ने भागवत को आगाह किया था और उनसे सख्ती बरतने को कहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मोदी जहां खुद को भाजपा और भारत के लिए राजनीतिक रूप से अपरिहार्य साबित करने पर तुले हुए हैं, वहीं भागवत हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने में आरएसएस की अजेयता को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के विश्लेषण से अधिक उपयुक्त तरीका और कुछ नहीं हो सकता। जहां मोदी और उनके सहयोगियों ने इन राज्यों में भाजपा की जीत को मोदी के करिश्मे से जोड़ा, वहीं आरएसएस ने दावा किया है कि इन चुनावी जीत का श्रेय आरएसएस के कार्यकताओं को जाता है। मोदी और भागवत के बीच ताजा सत्ता संघर्ष बिहार की मतदाता सूची संशोधन के मामले में सामने आया है। आरएसएस ने मोदी के कदम का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया है, लेकिन वह इसका समर्थन भी नहीं करता है। मोदी ने पहले ही बिहार में इस योजना को बड़े जोर-शोर से शुरू कर दिया है। आरएसएस नेताओं के अनुसार भी इस कदम का शिकार ईबीसी और दलितों की बड़ी आबादी होगी, जो आरएसएस के निशाने पर हैं। यह लगातार इन वर्गों को यह विश्वास दिलाता रहा है कि वे हिंदू हैं। गांवों में जाकर गणना करने वाले लोग उनके मूल निवासी होने के दावों के प्रमाण के रूप में मूल जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। यह एक खुला रहस्य है कि इनमें से एक बड़ी आबादी के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। जाहिर है कि उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान खोने का खतरा है। एक बार जब उन्हें राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया जाता है, तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी स्वतः ही छीन लिया जायेगा। यह स्पष्ट है कि मोदी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाल ही में हुए चुनावों में उनकी निष्ठा बदली हुई, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में दिखी जिससे मोदी को यह कड़ा संदेश गया है कि दलित और ईबीसी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मोदी का यह चुनावी कदम उन्हें मध्यम वर्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और उनके बीच अपने समर्थन आधार को मजबूत करने में मदद करेगा। लेकिन इससे आरएसएस के राजनीतिक हित खतरे में पड़ जायेंगे, जो उन्हें हिंदू के रूप में पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसका भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आरएसएस की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस शताब्दी समारोह के दौरान अपनी योजना की घोषणा करने के लिए दृढ़ था।

जिला कारागार व पुलिस लाइन में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर

हिन्दी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र जनता का सच ब्यूरो चीफ रामेश्वर सिंह भदौरिया बहराइच

बहराइच। नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार के निर्देश पर जिला कारागार बहराइच में आयोजित जागरूकता शिविर में जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों को नशीली दवाओं व अन्य नशा का सेवन न किये जाने हेतु शपथ दिलायी गयी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 जून को नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ''बाधाओं को तोड़नारू सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुर्नप्राप्ति'' की थीम निर्धारित की गई है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/पंचम अपर जनपद न्यायाधीश विराट शिरोमणि ने बताया कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाली हानियों से आमजन को जागरूक करना, ड्रग्स तस्करी के वैश्विक नेटवर्क के विरूद्ध कार्यवाही में सहयोग को प्रेरित करना तथा युवाओं और बच्चों को नशे की लत से दूर रखना तथा नशा मुक्ति और पुनर्वास केन्द्रों के लिए समर्थन जुटाना है। श्री शिरोमणि ने बताया कि इसके अतिरिक्त पुलिस लाईन में आयोजित जागरूकता शिविर में प्रशिक्षु आरक्षियों को नशे की रोकथाम की शपथ भी दिलाई गई।

जनपद बहराइच सिलौटा, तप्पेसिपाह व बौण्डी में सम्पन्न हुआ बाढ़ से बचाव व राहत कार्यों का मेगा मॉकड्रिल

हिन्दी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र जनता का सच ब्यूरो चीफ रामेश्वर सिंह भदौरिया

बहराइच। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने के उद्देश्य से तहसील महसी के ग्राम बौंडी स्थित सिलौटा के रामघाट पर मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, तहसील कैसरगंज के ग्राम तप्पेसिपाह स्थित घाघराघाट पर अति. मजिस्ट्रेट प्रथम राम दयाल तथा तहसील नानपारा के ग्राम बौण्डी में उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा (मोतीपुर) प्रकाश सिंह के नेतृत्व में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन कर जिला प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियों को परखा गया।

ग्राम सिलौटा में आयोजित मॉक ड्रिल की पटकथा के अनुसार घटना स्थल सिलौटा रामघाट पर घाघरा नदी में एक नाव पलट जाती है। नाव में सवार सभी लोग डूबने लगते हैं और खुद को बचाने के ज़ोर–ज़ोर से बचाव–बचाव की आवाज़ निकालने लगते हैं। डूबते लोगों की मदद की पुकार सुनकर पलक झपकते ही निरीक्षक दीपक मण्डल के नेतृत्व में एन.डी.आर.एफ. 11वीं बटालियन के जवान मोटरबोट पर सवार होकर नदी के बीच पहुंच गये और लाइफब्वाय को पानी में फेंककर डूबते हुए लोगों को मोटरबोट में सवार कर उन्हें सुरक्षित नदी के किनारे लेकर आये।

नदी से रेस्क्यू किये गये लोगों को तत्काल स्ट्रेचर पर लेटा कर मेडिकल कैम्प में लाया गया जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा बचाये गये लोगों की जांच व प्राथमिक उपचार

कर उन्हें स्ट्रेचर के सहारे ही पास खड़ी एम्बुलेन्स पर सवार कराया। जीवनरक्षक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेन्स पर मौजूद चिकित्सकों ने भी तत्काल पीड़ित व्यक्तियों को साथ लेकर चिकित्सालय की ओर रवाना हो गये। रामघाट पर मुख्य राजस्व अधिकारी/इन्सीडेन्ट कमाण्डर व प्लानिंग सेक्शन चीफ देवेन्द्र पाल सिंह के नेतृत्व में सम्पन्न माकड्रिल इतना जीवन्त था कि नदी के आस–पास मौजूद ग्रामीण इसे वास्तविक घटना समझ रहे थे। परन्तु जब उन्हें पता चला कि यह मात्र राहत व बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास था तो चेहरे पर दिखने वाला तनाव खत्म हुआ। मॉकड्रिल के दौरान पशुओं के रेस्क्यू का भी रिहर्सल किया गया।

मॉकड्रिल स्थल पर मुख्य राजस्व अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य यह है कि हम वास्तविक आपदा आने से पूर्व ही उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हुए राहत व बचाव कार्यों को सम्पन्न कराकर अपनी तैयारियों को परख लें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा मॉक ड्रिल के लिए बेहतर तैयारी की गयी है। उन्हें विश्वास है कि यदिसी वास्तविक आपदा जैसी कोई परिस्थितियॉ उत्पन्न होती हैं तो सभी विभाग बेहतर कार्य कर सकेंगे। श्री सिंह ने मॉकड्रिल में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों, एनसीसी, पीआरडी, एनएसएस, आपदा मित्र, मेरा जुड़ा भारत, आपदा ट्रेनर्स, सुरक्षा एजेन्सियों के जवानों तथा मॉकड्रिल में सभी प्रतिभागी सहयोगियों का आभार ज्ञापित करते हुए ग्रामवासियों से अपील की कि मॉकड्रिल के दौरान बतायी गई बातों को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आपदा के दौरान जानी व माली नुकसान को न्यून से न्यूनतम किया जा सके।

मॉकड्रिल के उपरान्त मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों ने अन्य सम्बन्धित के साथ स्टेजिंग एरिया कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बौण्डी में आपदा प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न विभागों यथा राजस्व, नागरिक सुरक्षा, मानव एवं पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद एवं शिक्षा विभाग द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी पण्डालों का निरीक्षण कर बाढ़ के समय विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। घटना स्थल पर खाद्यान्न किट एवं पशुओ के लिए चारा एवं भूसा वितरण कार्य का डैमो भी प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त उप जिलाधिकारी महसी अश्वनी पाण्डेय, पुलिस क्षेत्राधिकारी डी.के. श्रीवास्तव व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मौजूद ग्राम वासियों को बाढ़ के पूर्व व बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के पश्चात् बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी राजकुमार, डीपीआरओ सर्वेश कुमार पाण्डेय, एआरटीओ प्रवर्तन ओ.पी. सिंह, जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव, खण्ड विकास अधिकारी महसी हेमन्त यादव, तहसीलदार विकास कुमार, कमाण्डेन्ट ताज रसूल, थानाध्यक्ष तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

जनपद बहराइच नाबालिग से दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त बाद मुठभेड़ गिरफ्तार

01 अदद तमंचा 315 बोर मय फायरशुदा कारतूस बरामद

हिन्दी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र जनता का सच स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर नानपारा बहराइच

थानाः– रुपईडीहा/स्वॉट

पुलिस अधीक्षक बहराइच के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी महोदय नानपारा के पर्यवेक्षण में थाना रुपईडीहा पुलिस व स्वॉट की संयुक्त टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को बाद मुठभेड़ किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 26.06.2025 को थाना रुपईडीहा पुलिस व स्वाट/एसओजी की संयुक्त टीम को दिनांक 25.06. 2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के वांछित अभियुक्त अजमेर पुत्र गुलाम वारिश के सम्बन्ध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई जिसके क्रम में अभियुक्त के मिलने के संभावित स्थान नेपाल राष्ट्र बार्डर पर स्थित पचपकड़ी गांव से अभियुक्त की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी की गयी।

जिसपर अभियुक्त द्वारा जानलेवा हमले की नीयत से पुलिस पर फायर किया गया, पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षार्थ आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया, इस दौरान उसके एक पैर में गोली लग गयी । तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व मोबाइल बरामद हुआ । अभियुक्त अजमेर उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र गुलाम वारिश नि0 बढ़ैया दा0 अड़गोड़वा थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच को उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया । अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलति है।

व अभियुक्त का नाम

– अजमेर पुत्र गुलाम वारिश नि0 बढ़ैया दा0 अड़गोड़वा थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच उम्र करीब 22 वर्ष

व अभियोग का विवरण–

– मु0अ0सं0 190/2025 धारा 65(1)/115(2)/352 ठछै व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना रूपईडीहा बहराइच

– मु0अ0सं0 191/2025 धारा 109(1) ठछै व 3/25 ।तउे ।बज थाना रूपईडीहा बहराइच

व बरामदगी का विवरण दृ

– 01 अदद तमन्चा नाजायज .315 बोर व एक अदद नाल में फंसा हुआ फायर कारतूस .315 बोर

व गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान

– दिनांक 26.06.2025 समय 02.05 बजे रात्रि

– पचपकड़ी बार्डर रोड़ तिराहा थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

व गिरफ्तारी थाना रुपईडीहा पुलिस टीमः–

1. प्र0नि0 श्री रमेश सिंह रावत
2. उ0नि0 अशोक कुमार, चौकी इंचार्ज शिवपुर मोहरनिया
3. उ0नि0 यतीन्द्र सिंह, चौकी इंचार्ज चिकनिया
4. उ0नि0 संतोष कुमार यादव
5. हे0का0 उमेश यादव
6. का0 दीपचन्द यादव
7. का0 शिवेन्द्र कुमार वर्मा

व गिरफ्तारी स्वाट टीमः–

1. निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री सर्वजीत गुप्ता
3. आरक्षी विष्णू प्रताप सिंह

डीएम व एसपी ने नेपाल राष्ट्र के उच्चाधिकारीगण के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को–ऑर्डिनेशन कमेटी बैठक की

जनपद बहराइच भारत–नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट भवन, रुपईडीहा के सभागार में जिलाधिकारी बहराइच व पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा नेपाल राष्ट्र के उच्चाधिकारीगण के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को–ऑर्डिनेशन कमेटी बैठक की गयी पारस्परिक समन्वय, सीमा सुरक्षा और सीमा पार अपराधों की रोकथाम पर की गयी विस्तृत चर्चा

हिन्दी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र जनता का सच स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर नानपारा बहराइच

आज दिनांक 26.06.2026 को भारत–नेपाल सीमा की सुरक्षा, पारस्परिक समन्वय और सीमा पार अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में रूपईडीहा स्थित एकीकृत चेक पोस्ट में बार्डर डिस्ट्रिक्ट को–ऑर्डिनेशन कमेटी बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में जिलाधिकारी बहराइच, पुलिस अधीक्षक बहराइच, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारीगण, कमांडेंट एसएसबी 42वीं, 59वीं, 70वीं बटालियन, डीएफओ बहराइच व कतर्नियाघाट, जिला आबकारी अधिकारी, कस्टम विभाग व एटीएस के उच्चाधिकारी, सीमावर्ती थानों के प्रभारी निरीक्षक, नेपाल राष्ट्र से वर्दियां और बांके जिलों के सीडीओ व पुलिस अधीक्षक, नेपाल आर्म्ड फोर्सेस के उच्चाधिकारी आदि सम्मिलित हुए । बैठक के दौरान सीमा सुरक्षा व्यवस्था

को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों पर चर्चा की गई । विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त गश्त की योजना, गहन निगरानी व चेकिंग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीमा पर हो रही तस्करी, मादक पदार्थों व मानव तस्करी तथा आपराधिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु सूचना के त्वरित आदान–प्रदान और संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा तय की गई । साथ ही दोनों देशों के मध्य आपसी रिश्ते को अधिक दृढ़ करने, कानून एवं व्यवस्था तथा व्यापार को बढावा देने तथा विविध समस्याओं के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गयी । बैठक में जनपदीय पुलिस, नेपाल राष्ट्र की पुलिस,ैैठ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर दोनों देशों के मध्य आवागमन करने वालों की सघन चेकिंग, जाली कागजात के माध्यम से अवैध संचरण करने वाले अवांछनीय तत्व की आवाजाही, अराजक तत्वों की रोकथाम पर वार्ता की गयी। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र एवं पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की गयी, दोनों देशों ने सीमा से सटे वन्य क्षेत्रों में अवैध कटान, जानवरों की तस्करी और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर सहमति जताई । बैठक में भारत–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।

जनपद बहराइच थाना नानपारा क्षेत्र चौंकाने वाला मामला सामने कई मोहल्ला घसियारन टोला पीड़ित महिला रिहाना ने बताया है की मेरी माता का देहांत हो गया उसके बाद उसके चाचा और चाचा के लड़कों ने घर से बाहर कर दिया

हिन्दी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र जनता का सच ब्यूरो चीफ रामेश्वर सिंह भदौरिया

जबकि नगर पालिका में माता जी के नाम से और मेरे नाम घर टैक्स जमा किया गया है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण अभियान चला कर महिलाओं को जागरुक कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है पीड़ित महिला रिहाना दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला रिहाना के पास सभी वीडियो साक्षक मौजूद हैं। घर में घुसकर सभी सामान को निकाल कर फेंक दिया गया और घर से बाहर कर दिया गया पीड़ित महिला ने मीडिया कर्मियों से बात की और अपना दर्द बया किया है क्या वीडियो वायरल होने के बाद आलाअधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित महिला को हक दिलाया जाएगा की इसी तरह दर दर भटकती रहेगी।

लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही भाजपा सरकार : सत्यनारायण पटेल

कांग्रेस के जिला व महानगर कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण

अयोध्या। कांग्रेस पार्टी के जिला एवं महानगर कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में सम्पन्न हुआ। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण पटेल तथा पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण नारायण पटेल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कांग्रेस की वैचारिक प्रतिबद्धता, लोकतंत्र और संगठनात्मक अनुशासन के पालन की सीख दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह एवं महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने अपने संबोधन में संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने

भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, जिसका डटकर मुकाबला करना होगा।

पूर्व सांसद डॉ. निर्मल खत्री ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदान, संघर्ष और सेवा का रहा है। आज जब लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, तब कांग्रेस का हर सच्चा सिपाही संविधान और जनहित की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे कृ यही समय की मांग है। हमें सड़कों से लेकर संसद तक भाजपा की विघटनकारी नीतियों का विरोध करना होगा।" जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि "हमारा प्राथमिक उद्देश्य संगठन को गांव–गांव, वार्ड–वार्ड तक मज़बूत करना है। युवा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं, जिन्हें प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। महानगर कोऑर्डिनेटर अमित जायसवाल तथा अब्दुल्ला शेर खान ने कहा भाजपा की जनविरोधी, अलोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना ही कांग्रेस का लक्ष्य है।

महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने सभी आगंतुकों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि "यह संगठन केवल पदों से नहीं, बल्कि समर्पण और ईमानदारी से चलता है। हम सब मिलकर कांग्रेस की विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाएं और अयोध्या में मजबूत विकल्प बनकर उभरें।"

जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया कि इस अवसर पर प्रमुख रूप सेपूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह ,राजेंद्र प्रताप सिंह, अनीस अहमद, पूर्व विधायक माधव प्रसाद,उग्रसेन मिश्रा,करमराज यादव, दिनेश शुक्ला, आशुतोष सिंह, फूलचंद यादव, विकास सिंह विकी, विजयपाल सिंह,शैलेंद्र मणि पांडे, उमेश उपाध्याय, राम अवध पासी ,प्रताप बहादुर सिंह, राजकुमार पांडे, मुस्तफा खान, अनिल तिवारी, कमलासन पांडे, अंकुर खत्री, दयाशंकर तिवारी, उपेंद्र सिंह लल्लू, अकबर अली मेजर,अनिल सिंह, रामेंद्र त्रिपाठी,वसंत मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह रिशु, पूर्व महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर सुरेंद्र सिंह सैनिक, आशुतोष संडिल्य,प्रवीण श्रीवास्तव, रामकरण कोरी, डी एन वर्मा,डॉक्टर विनोद गुप्ता, महिपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह,भगवान बहादुर शुक्ला, श्रीमती ज्योति चौहान, नाजिश फातिमा, जयप्रकाश गुप्ता, हरजीत सलूजा, अशोक, धीरेंद्र नाथ वर्मा, मोहम्मद आरिफ, धीरेंद्र उपाध्याय द्वारकापांडे, राज प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, अशोक कुमार राय धीरेंद्र सिंह बबलू, रामकिशोर वर्मा, अमित पांडे, मोहम्मद दानिश आदि प्रमुख लोग थे।

साहित्यकार आशुतोष त्रिपाठी 'आलोक' को मिला 'नेपाल–भारत मैत्री सम्मान'

अयोध्या। बुलंदी अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था एवं राष्ट्रीयता संरक्षण अभियान नेपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चर्मण्वती साहित्य सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी अत्यंत गरिमामयी एवं सफल रही। यह आयोजन नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश, बैतड़ी जिले के डिलासैनी गाउँपालिका स्थित देवभूमि मानस खंड की पवित्र चर्मण्वती नदी के तट पर संपन्न हुआ। इस भव्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत से आए प्रतिष्ठित कवि आशुतोष त्रिपाठी 'आलोक' (अयोध्या, उत्तर प्रदेश) को "विशिष्ट अतिथि / कवि" के रूप में आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने अपने भावपूर्ण संगीतबद्ध काव्य पाठ से सभी का मन मोह लिया। उनकी सरस प्रस्तुति पर उन्हें "नेपाल–भारत मैत्री सम्मान" से सम्मानित किया गया, जो दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जिला न्यायाधीश तीर्थराज भट्ट (बैतड़ी जिला अदालत), तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नेपाल संविधान सभा की सदस्य आनंदी पन्त 'अनम' की मंचीय उपस्थिति रही, जिन्होंने सभी साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में डॉ. नारायणी भट्ट (कवयित्री एवं शिक्षाविद) राजेन्द्र जोशी (कैंपस प्रमुख)उत्तम बहादुर साउंद (वृद्ध आश्रम संचालक) भागीरथ अवस्थी (रेडियो पत्रकार) संतोष प्रकाश जोशी (डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष)हेमबाबू लेखक (राष्ट्रीयता संरक्षण अभियान अध्यक्ष) रमेश पंत 'मीतबंधु (वरिष्ठ कवि नेपाल) कविराज भट्ट (कवि,नेपाल)नागेन्द्र त्रिपाठी (वरिष्ठ कवि,भारत)सहित अनेक उत्कृष्ट कवि व रचनाकार सम्मिलित रहे।

इस अवसर पर आशुतोष त्रिपाठी 'आलोक' ने कहा कि "नेपाल की पुण्यभूमि पर हिंदी काव्य पाठ कर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, अपितु भारत–नेपाल सांस्कृतिक समरसता का सम्मान है।"इस भव्य आयोजन में उपस्थित सभी रचनाकारों की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय रही। भारत–नेपाल की सांस्कृतिक मैत्री को सशक्त बनाने वाला यह सम्मेलन साहित्यिक इतिहास में एक स्मरणीय अध्याय बन गया।

प्रदेश के इकॉनमिक ग्रोथ के बैकबोन हैं एक्सप्रेस-वे-योगी

सीएम ने की 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर की शुरुआत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास से प्रदेश के 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) की ऐतिहासिक शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे को प्रदेश की इकॉनमिक ग्रोथ का बैकबोन बताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब यूपी में एक साथ 5 एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 13,240 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आईएमएलसी की स्थापना हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस लॉन्चिंग को प्रसन्नता का क्षण बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का हिस्सा बताया, जिसमें उत्तर प्रदेश को देश के औद्योगिक विकास का केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश को %एक्सप्रेसवे प्रदेश% के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि आज यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के सभी 6 नोड भी एक्सप्रेसवे के किनारे ही विकसित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने आईएमएलसी को नये भारत के नये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताया। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए सुरक्षा, लैंडबैंक और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पहली शर्त होती है और उत्तर प्रदेश ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं इस पर सफर किया, जो तेज रफ्तार के साथ-साथ आरामदायक भी था। सीएम ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को कभी पिछड़ा माना जाता था, जहां निवेशक आने से हिचकते थे, वहां आज आईएमएलसी के रूप में एक बड़ा सपना साकार हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योगों और फैक्ट्रियों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में विकसित करना होगा, ताकि स्थान का अधिकतम उपयोग हो सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएमएलसी पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदलेगी, बल्कि वैश्विक निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आईएमएलसी के निर्माण में मैनपावर की कोई कमी न हो और निवेशकों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम योगी ने आईएमएलसी के लॉन्चिंग इवेंट के दौरान प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे किनारे विकसित किए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर्स पर भी जारी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

आउटसोर्स सेवा निगम की मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा। गुरुवार को सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित निगम की कार्यप्रणाली, संरचना और दायरे पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार श्रमिकों के श्रम, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विकेन्द्रीकृत तरीके से होता है, जिसके कारण समय पर वेतन न मिलना, वेतन में कटौती, ईपीएफ/ईएसआई लाभों से वंचित रहना, पारदर्शिता की कमी और उत्पीड़न जैसी अनेक शिकायतें मिलती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक है।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक ऽबोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सऽ और एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए किया जाएगा।

लखनऊ में बनेगा प्रदेश का पहला बीज पार्क

कृषि मंत्री ने बीज उद्यमियों संग की बैठक

लखनऊ। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधान भवन के समिति कक्ष संख्या-8 में बीज प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह बीज पार्क की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और नियमों, शर्तों एवं सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 35 बीज कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने प्रतिक्रियाएं साझा कीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला बीज पार्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पार्क प्रदेश को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगा। उद्यमियों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह बीज पार्क लखनऊ जनपद के मालिहाबाद क्षेत्र स्थित अटारी, नवबस्ता एवं सुरती खेड़ा गांवों में कुल 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। यह भूमि राज्य कृषि फार्म के अंतर्गत आती है। इस पार्क में कुल 26 औद्योगिक भूखंड विकसित किए जाएंगे, जो विभिन्न आकारों में होंगे और उन्हें 30 वर्ष की लीज पर, 90 वर्ष तक बढ़ाई जा सकने की सुविधा के साथ, बीज उत्पादन से जुड़ी संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा।बीज पार्क में आंतरिक सड़कों, विद्युत, जल, सीवरेज, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण हॉल, बीज प्रयोगशाला, परीक्षण एवं भंडारण की साझा सुविधाएं, गेस्ट हाउस और हरित क्षेत्र जैसी अधोसंरचनाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही आईसीएआर तथा कृषि विश्वविद्यालयों को ज्ञान भागीदार के रूप में जोड़ा जाएगा तथा राष्ट्रीय शोध संस्थानों से तकनीकी मार्गदर्शन और परीक्षण सहयोग लिया जाएगा।बीज पार्क में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसमें भूमि पंजीकरण पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क माफी, बीज इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक और हाइब्रिड लैब, स्पीड ब्रीडिंग व बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपये तक) शामिल है। साथ ही, बीज प्रसंस्करण इकाइयों को 10 वर्षों के लिए बिजली शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति कृषि विभाग द्वारा यूपीपीसीएल को की जाएगी। भूखंडों का आवंटन पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

जल जीवन मिशन में टंकियां भाजपा के भ्रष्टाचार को सह नहीं पा रही-अखिलेश

प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त-डिम्पल यादव

लखनऊ। मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने कामकाज से सभी को निराश किया है। भाजपा ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं से सम्बन्धित जो वादे किये थे उन्हें पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मंहगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। महिलाओं को रोज अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ रहा है। यह बातें उन्होंने गोरखपुर में पत्रकारों से बातें के दौरान व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि विरासत गलियारा में उजाड़े गए व्यापारियों का दुःख दर्द जानने के लिए जा रहे नेता विरोधी दल विधानसभा माता प्रसाद पाण्डेय और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव को प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया। वे व्यापारियों से न मिल पायें इसलिए बुलडोजर के साथ भाजपाइयों ने घेराव किया। यह कहने के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उल्लेखनीय हो कि सांसद श्रीमती डिम्पल यादव के गोरखपुर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम के आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं/नेताओं द्वारा स्वागत किया गया।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में रिकार्ड भ्रष्टाचार हो रहा है। जल जीवन मिशन में टंकियां भाजपा के भ्रष्टाचार का बोझ सह नहीं पा रही हैं। हर महीने पानी की टंकियां फट रही हैं। इस सरकार ने गांव-गांव के रास्ते खोद दिए हैं लेकिन पानी कहीं नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान, आरक्षण, सेकुलरिज्म और समाजवाद की विरोधी है। भाजपा वोट के डर से आरक्षण और संविधान के खिलाफ सीधे न बोलकर समाजवाद और सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलती है। भाजपा अपने स्वभाव काल का प्रस्ताव भूल गयी है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर जनता जागरूक हो गयी है। जनता जानती है कि जातीय जनगणना होने से उसे हक और अधिकार मिलेगा। इसी से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा और उसकी विचारधारा के लोग सेकुलरिज्म, समाजवाद और संविधान पर हमले कर रहे हैं। यह बातें उन्होंने गुरूवार को आजमगढ़ में नये पार्टी कार्यालय भवन का उद्घाटन और पार्टी कार्यालय परिसर में सम्मेलन और बैठक हाल का शिलान्यास करने के दौरान उमड़ी भीड़ को सम्बोधित करते हुये व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से पार्टी का भावनात्मक लगाव है। आजमगढ़ की जनता ने पार्टी के हर फैसले का सम्मान किया और साथ दिया। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी रही हो आजमगढ़ ने हमेशा पार्टी को मजबूती दी। नेताजी को लोकसभा पहुंचाया धर्मेन्द्र यादव जीते। आजमगढ़ से समाजवादियों का पुराना और गहरा रिश्ता है यह विचारधारा का सम्बंध है। यहां पास से जो एक्सप्रेस-वे जा रहा है। यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ से एक तरफ आजमगढ़ तो दूसरी तरफ सैफई को जोड़ता है। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब डॉ.भीमराव अम्बेडकर, डॉ.राममनोहर लोहिया व श्रद्धेय नेताजी ने देखा और जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर चलकर हम लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे और अपने पीडीए परिवार के लोगों को हक और सम्मान दिलाएंगे। श्री यादव ने कहा कि पीडीए यही है जिसे हम सब बहुजन समाज कहते थे। पीडीए पीड़ित, दुःखी अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। उन्होंने कहा कि पीडीए एकता हमारी ताकत है। पीडीए एकता सरकार बनाएगी और सामाजिक न्याय का रास्ता खोलेगी। भाजपा के लोग पीडीए की एकता से घबराये हुए हैं। उनका व्यवहार भाषा और बोली बदल गयी है। भाजपा से सावधान रहना है। ये षडयंत्रकारी है। पीडीए को अपमानित करते हैं।

यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशासनिक बदलावों के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस.बी. शिरडकर ने पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड की कमान सभाल ली है उन्हें यह जिम्मेदारी डीजी के रूप में मिली है। अभी तक वह लखनऊ ज़ोन के अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात थे। प्रोन्नति के बाद वह अब पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बने है। यह नियुक्ति पुलिस महकमे की रीढ़ माने जाने वाली भर्ती और प्रोन्नति प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एस.बी. शिरडकर उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठतम और भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं। लखनऊ ज़ोन की कमान संभालते हुए उन्होंने न केवल कानून व्यवस्था को सशक्त किया, बल्कि कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। इससे पहले वह लखनऊ के पुलिस आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और खुफिया विभाग में भी सेवाएं दे चुके हैं।

यूपी में शरिया कानून लागू करना चाहती है सपा-बृजेश पाठक

लखनऊ। देश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालु सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस साल भी 11 जुलाई से पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू होगी। आरोप है समाजवादी नेताओं ने कांवड़ यात्रियों की तुलना आतंकियों से कर दी। इस बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आतंकियों की तुलना कांवड़ यात्रियों से करना बेहद निंदनीय है। समाजवादी पार्टी यूपी में शरिया कानून लागू करना चाहती है। मुस्लिम तुष्टिकरण का बढ़ावा देकर वोट बैंक बनाना चाहते है। प्रदेश की जनता सपा के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकान पर नाम लिखवाने को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो सरकार का अधिकार है कि वह दुकानदार का नाम जाने। हमारी सरकार सकुशल कांवड़ यात्रा निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। हर धार्मिक यात्रा को लेकर हमारी सरकार अति संवेदनशील है। कानून व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दुकानदारों के लिए खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी को भगवान का नाम अपनी दुकान पर नहीं दिखेगा और उसे सजा भुगतनी पड़ सकती है। हालांकि इस तरह के निर्देशों को लेकर कोई कानून स्पष्ट नहीं है लेकिन सरकार की ओर से यह निर्देश प्रशासनिक तौर पर जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है। तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत विधिपूर्वक घोषित आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाएगा और ऐसे में 3 महीने की कैद या एक हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही सजाएं संभावित हैं।

तीन आईपीएस अफसरों के किये तबादले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत राज्य के प्रमुख पुलिस पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं।आईपीएस मुथा अशोक जैन को गोरखपुर ज़ोन का नया अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में एडीजी के पद पर कार्यरत थे। अब वे गोरखपुर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, पीसी मीणा को पुलिस महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह आर्थिक रूप से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूर्णकालिक डीजी कारागार बना दिया गया है। इसके तहत वह प्रदेश की जेल प्रणाली की निगरानी और सुधार कार्यों को गति देंगे इसके अलावा, डॉ. के एन प्रताप कुमार को पुलिस महानिदेशक (सीएमडी), पुलिस आवास निगम की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह गोरखपुर ज़ोन में कार्यरत थे। अब वह प्रदेश में पुलिस आवास निर्माण, सुधार और संबंधित परियोजनाओं को संभालेंगे। इन तबादलों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है।

लोकभवन में कैबिनेट के पश्चात प्रेस वार्ता में बोलते संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना व अन्य।

मुड़िया पूर्णिमा मेला पर चलेंगी 1000 अतिरिक्त बसें

लखनऊ। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कल से मथुरा में शुरू हो रहे मुड़िया पूर्णिमा मेला को प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा की दृष्टिगत इस क्षेत्र में 1000 अतिरिक्त बसों का संचालन राज्य परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। आगरा क्षेत्र से 250 बसें, अलीगढ़ क्षेत्र से 150 बसें, गाजियाबाद क्षेत्र से 150 बसें, मेरठ क्षेत्र से 100 बसें ,इटावा क्षेत्र से 150 बसों का संचालन किया जाएगा।

नियामक आयोग में जनसुनवाई में शामिल होकर करेंगे निजीकरण का विरोध

जनपदों और परियोजनाओं में सभायें कर जेल भरो अभियान की तैयारी

लखनऊ। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए निजीकरण के मसौदे के विरोध में संघर्ष समिति जन सुनवाई की सभी तारीखों पर नियामक आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग करेगी। यह निर्णय गुरुवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है।

जारी बयान में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अवैधानिक ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा तैयार किए गए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रारूप मसौदा असंवैधानिक है। संघर्ष समिति ने निजीकरण के मसौदे को पर बिंदुवार आपत्तियां तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी जनसुनवाई के दौरान सभी शहरों में उपस्थित रहेंगे और निजीकरण के विरोध में हर जगह आपत्ति दर्ज की जाएगी और निजीकरण निर्णय रद्द करने की मांग की जाएगी। पदाधिकारियों ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग 07 जुलाई को लखनऊ में, 09 जुलाई को कानपुर में, 11 जुलाई को वाराणसी में, 15 जुलाई को आगरा में, 16 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में और 17 जुलाई को मेरठ में सुनवाई करने वाला है। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान निजीकरण का विरोध कर स्वेच्छा से जेल भरो आंदोलन में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों की सूची बनाया जाना प्रारंभ हो गया। संघर्ष समिति ने निर्देश दिया है कि तीन दिन के अंदर सभी जनपदों से जेल भरो आंदोलन में स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों का कम से कम सात दिन तक जेल भरो अभियान की योजना बनाकर सूची तैयार कर ली जाय।

डिग्री कालेजों में सहायक आचार्य पद के लिये अब देनी होगी लिखित परीक्षा

लखनऊ। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गुरूवार को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लोक भवन में मीडिया जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि पहले आचार्यों की भर्ती योग्यता के अनुसार साक्षात्कार के आधार पर कर ली जाती थी किन्तु भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी देनी होगी,जिसमें लिखित परीक्षा के अंक ज्यादा होंगे और साक्षात्कार के अंक कम होंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यार्थियों में विश्वशनीयता बढ़ेगी।। उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सुधारों की दिशा में यह निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश में निजी क्षेत्र के एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों और संस्थागत विस्तार पर विशेष बल दिया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय डॉ.केएन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फॅर्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट द्वारा ग्राम बिसोखर व बेगमाबाद बुदाना, तहसील-मोदीनगर में 20.45 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। इस मिशन का उद्देश्य न केवल राज्य के युवाओं को देश में रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विदेशों में भी नियोजन के अवसर दिलाना है वह भी अब सीधे राज्य सरकार के माध्यम से। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह दूरदर्शी पहल न केवल प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत का वैश्विक मानव संसाधन आपूर्ति केंद्र (ग्लोबल एचआर हब) बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। यह मिशन राज्य सरकार के उस वादे की पुष्टि करता है जिसमें कहा गया था हर हाथ को काम और हर हुनर को सम्मान।

बुन्देलखण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अर्थॉरिटी एरिया नियोजन नियमावली की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने बुन्देलखण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अर्थॉरिटी एरिया प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान विनियमावली.2025 के अंग्रेजी एवं हिन्दी की विधीक्षित अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कराकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारीए बीडा को निर्देशित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बहुआयामी विकास हेतु नोएडा की तर्ज पर एक नयी इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए शासकीय अधिसूचना संख्या. 5595/77.4.23.1372.23 दिनांक 14.09.2023 द्वारा बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम.1976 यथासंशोधित में विहित प्राविधानों के अधीन बीडा के अधिसूचित क्षेत्र के भू.उपयोग के सुनियोजित विकास हेतु समुचित योजना तैयार किए जाने के लिए बुन्देलखण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अर्थॉरिटी एरिया प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान विनियमावली.2025 बनाया जाना आवश्यक है। इस विनियमावली के लागू होने से सुरक्षित निर्माण, भवन की डिजाइन और आकार को नियंत्रित करने, अनियोजित विकास को रोकने, पर्यावरण पर निर्माण के विपरीत प्रभाव को रोकने के साथ-साथ पर्याप्त जन सुविधाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, आवागमन हेतु पर्याप्त चौड़ाई की सड़कों, शहर के घनत्व के अनुपात में पार्किंग एवं हरित क्षेत्र हेतु जन.सामान्य के अनुकूल शहर का विकास होगा। औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र के विकास एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

क्रय अनिवार्यता को 31 मार्चए 2028 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0ए उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओंए गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम द्वारा उत्पादित वस्त्रों को पूर्व प्रचलित क्रय अनिवार्यता की व्यवस्था की अवधि को 31 मार्च, 2028 तक निर्धारित शर्तों के अधीन बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने लघु एवं कुटीर इकाइयों के विकास तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों के हित के दृष्टिगत सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमोंध्निगमोंध्प्राधिकरणोंध्परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं एवं गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम द्वारा लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता की व्यवस्था को निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया है।

कम्प्यूटिंग को नामांकन के आधार पर अनुबन्धित किए जाने का प्रस्ताव पास मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार की समेकित वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली इण्टीग्रेटेड फानेन्शियल मैनेजमेण्ट सिस्टम.प्थ्डैद्ध के उन्नयन हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था.सेण्टर फॉर डेवलपमेण्ट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग ;ब्क्।ब्द्ध को नामांकन के आधार पर अनुबन्धित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। प्रस्तावित निर्णय से वित्त विभाग को अनेक लाभ प्राप्त होंगे। वर्तमान में प्रशासकीय विभागों से बजट प्रस्ताव तैयार कर मैनुअली वित्त विभाग को प्रेषित किए जाते हैं, जिनके संकलन में समय लगता है। प्रस्तावित व्यवस्था से बजट प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किए जा सकेंगे, जिससे समय व कागज की बचत होगी। वित्त विभाग का एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगाए जिसमें महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनाएं प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली ;एम0आई0एस0द्ध के रूप में उपलब्ध रहेंगीए जो निर्णय लेने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी। वेण्डर मैनेजमेण्ट सिस्टम में विभिन्न कार्यध्सेवा प्रदान करने वाले वेण्डर्स का पंजीकरण कर उनका डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसका उपयोग राज्य सरकार के समस्त विभाग कर सकेंगे। इस मॉड्यूल के माध्यम से वेण्डर्स अपने दावों का अनुश्रवण ऑनलाइन कर सकेंगे।

भाषा संस्थान के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थानए भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन स्वशासी संस्थान है। संस्थान के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की माँग कार्मिकों द्वारा निरन्तर की जाती रही है। भाषा विभाग के ही नियंत्रणाधीन अन्य स्वशासी संस्थानों के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जा चुकी है।

यूपी के आम को मिलेगी ग्लोबल पहचान-दिनेश सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव को संस्कृति, संस्कार एवं विरासत का अनूठा महोत्सव बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस महोत्सव में उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के बागानों के आमों की किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा। ये महोत्सव प्रदेश के किसानों की समृद्धि के द्वार खोलने तथा उनके जीवन में मिठास लायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आम एवं आम से बने उत्पादों को देश-विदेश मे भेजने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दुगुनी करने के संकल्प को प्रदेश की योगी सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार उपलब्ध कराकर पूरा करने का प्रयास कर रही है। तीन दिवसीय आम महोत्सव का शुभारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री लंदन, दुबई के लिए आम के कंटेनर को रवाना करेंगे। उक्त बातें प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने अपने सरकारी आवास में आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कही।श्री सिंह ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में उद्यान विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन हुये हैं, जिसमें किसानों की फसलों के उत्पादन से लेकर उसके लिए उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कर इसके माध्यम से प्रदेश के किसानों के फसलों को दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। योगी सरकार में पहली बार औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया है, गोष्ठियों के माध्यम औद्यानिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि औद्यानिक फसलों के माध्यम से कम क्षेत्रफल मे अधिक मूल्य की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसी तर्ज पर औषधि, फल-फूल, मसाले आदि की फसलों को किसानों को उगाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उद्यान विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक मण्डल पर औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी आयेजित करने का निर्णय लिया गया है। योगी सरकार द्वारा किसानों के उत्पादों को दुनिया के बाजारो में कम लागत में पहुंचाने के लिए जेवर एयरपोर्ट तैयार है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।
सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।